ISSN 2395-051X

# नियोजन काल में भारत का आर्थिक विकास

डॉ. आनंद तिवारी

प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग

शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

**सारांश -**

*भारत विश्व का प्रजातंत्रिक राष्ट्र है भारत ने विकास के मिश्रित अर्थव्यवस्था का मार्ग चुना नियोजितकाल भारत का स्वर्ग युग कहा जाये तो अंतिशयोक्ति पूर्ण न होगा । विकास का प्रत्येक क्षेत्र चाहे कृषि हो, उद्योग हो या सेवा क्षेत्र हो, निश्चित एवं निर्विवाद रूप में नियोजनकाल में सभी क्षेत्रों में समग्र सर्वांगीण एवं समन्वित विकास को नई दिशा एवं दशा मिली कृषिक्षेत्र के अंतर्गत हरितक्रांति, उद्योगक्षेत्र के अंतर्गत वृहद एवं मध्यम एवं लघु उद्योगो की स्थापना तथा सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ एवं जनकल्याण की दिशा में उल्लेखनीय विकास कार्य रेखांकित करने योग्य है 1991 में अर्थिक उदारीकरण में सेवा क्षेत्र में निर्णायक वद्धि निश्चित रूप से महत्वपूर्ण रही है योजना काल में अर्थिक विकास एवं वद्धि के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बड़े है नीतिआयोग के गठन के पश्चात् भारत में नई दिशा में विकास का मार्ग प्रशस्त किया है।*

**मुख्य शब्द** - पूंजीवाद, हरितक्रंति, उदारीकरण, अद्योसंरचनात्मक

समूचे विश्व में भारत सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक राष्ट्र है जिसने अपने विकास हेतु पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों व्यवस्थाओं को मिश्रित रूप में अंगीकार किया। आजादी के बाद भारत के संतुलित, समन्वित, एकीकृत, संघनित, समावेशी एवं सर्वांगीण विकास की आवश्यकता थी जिसे कार्य रूप में क्रियान्वयन हेतु नियोजित विकास की आवश्यकता थी।

भारत ने नियोजित विकास के मॉडल के रूप में पंचवर्षीय योजनाओं को वर्ष 1951 से अपनाया गया। जिसके अंतर्गत कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, उद्योग, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारिता आदि विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्य सुनिश्चित किये गये और प्रतिवर्ष हेतु लक्ष्य तथा प्रस्तावित व्यय का निर्धारण कर वास्तविक उपलब्धियों की निर्धारित लक्ष्य से तुलना कर अगले वर्ष में विचलनों को समाप्त कर आगली योजना में पुनः लक्ष्य निर्धारित किये गये ।

पंचवर्षीय योजनाकाल का युग वारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) तक था। भारत के चहुँमुखी एवं वहुआयामी विकास का युग कहा जा सकता है। कृषि, ग्रामीण-विकास, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य वृहद एवं लघु उद्योग की स्थापना, सिंचाई परियोजनाओं का विकास था परिवहन, यातायात, संदेशवाहन, व्यापार व्यवसाय तथा सेवा क्षेत्र में खाद्यान्न आत्मनिर्भरता, विदेशी व्यापार में गरीबी उन्मूलन एवं वेरोजगारी समाधान में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्णायक योगदान रहा है-

ISSN 2395-051X

## प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56)

प्रथम पंचवर्षीय योजना का बुनियादी उद्देश्य कृषि विकास रखा गया। साथ ही प्राथमिक क्षेत्रों के विकास का लक्ष्य रखा गया। सिंचाई तथा ऊर्जा पर 27.2% परिवहन तथा संचार पर 24% कृषि तथा सामुदायिक विकास पर 17.4% तथा सामाजिक सेवाओं पर 16.6% राशि व्यय की गई। इस योजना में आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.1% रखा गया परंतु उपलब्धि 3.6% रही। जिसका कारण मानसून की अनुकूलता का होना भी रहा है। तीन महत्वपूर्ण सिंचाई योजनायें भाखड़ा नांगल, हीराकुण्ड तथा दामोदर घाटी योजना प्रारंभ हुई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा पाच आई.आई.टी. की स्थापना की गई विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से स्वास्थ्य तथा मृत्यु दर में कमी की दिशा में कार्य प्रारंभ किया गया।

## द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश का औद्योगिक विकास करना रखा पांच स्टील प्लांट भिलाई, दुर्गापुर तथा राहुलकेला में रूस, ब्रिटेन तथा पश्चिमी जर्मनी की सहायता से स्थापित किए गए। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फन्डामेंटल रिसर्च तथा ऑटोमेटिक इनर्जी कमीशन ऑफ इण्डिया की स्थापना की गयी। कोयला उत्पादन तथा रेल्वे लाईन विस्तार में वृद्धि हुई। आर्थिक वृद्धि का 4.5% निश्चित किया गया वास्तविक उपलब्धि 4.27% हुई।

## तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66)

तृतीय पंचवर्षीय योजना में दो आर्थिक संकट उत्पन्न हुए 1965 में पाकिस्तान से युद्ध तथा 1966 में अकाल। इन कारणों ने देश के समक्ष खाद्यान्न संकट पैदा कर दिय। पंजाब राज्य में कृषि उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई सीमेंट तथा रंसायन उद्योगों की स्थापना हुई। राज्य विद्युत बोर्ड, ग्रामीण अंचलों में प्राथमिक विद्यालय तथा पंचायती निर्वाचन प्रारंभ हुआ। आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य 5.6% रखा गया वास्तविक उपलब्धि 2.4% रही।

## वार्षिक योजनायें (1966-69)

1966-67 में अकाल के कारण खाद्यान्न संकट पैदा हो गया। पाकिस्तान से युद्ध के कारण संसाधनों में कमी तथा मुद्रा स्फीति में वृद्धि के कारण सरकार को दो बार मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ा। 1966-67, 67-68 तथा 68-69 में वार्षिक योजनायें लागू की गई जिनमें प्रस्तावित व्ययों को व्यय किया गया।

## चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-1974)

प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने हेतु हरित क्रांति को अपनाया गया। 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ 18 मई 1974 को राजस्थान में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया आर्थिक विकास दर का लक्ष्य 5.6% रखा गया जबकि वास्तविक उपलब्धि 3.3% रही।

## पंचम पंचवर्षीय योजना (1974-78)

पांचवी योजना में रोजगार गरीबी तथा सामाजिक न्याय को आधार मानकर लक्ष्य निर्धारित किए गए। कृषि उत्पादन तथा रक्षा क्षेत्र के साथ-साथ 1971 में 21 बिंदु कार्यक्रम लागू किया गया। जीवनस्तर में सुधार हेतु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी क्रियान्वित किया गया। परिवहन क्षेत्र में विस्तार हेतु भारतीय राष्ट्रीय हाईवे प्रणाली आरंभ की गयी। आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य 4.4% रखा गया वास्तविक उपलब्धि की दर 4.8% रही।

## रोलिंग योजना (1978-1980)

जनता सरकार के हटने के पश्चात् कांग्रेस सरकार ने अपनी नई योजना क्रियान्वित की। जिसमें पृथक से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए देश के हित में रोलिंग प्लान का कोई लाभ नहीं मिल सका।

## षष्ठम पंचवर्षीय योजना (1980-1985)

छठवीं योजना मूलतः कीमत स्तर में कमी जीवन स्तर में सुधार हेतु मुक्त व्यापार नीति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्रियान्वित की गई। ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्र में ऋण तथा वित्तीय अनुदान हेतु 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई। जनाधिक्य की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए परिवार नियोजन कार्यक्रम पर बल दिया गया। आर्थिक वृद्धि दर निर्धारित लक्ष्य 5.2% के विरूद्ध वास्तविक 5.7% रहा।

## सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90)

सातवीं योजना के तीन प्रमुख उद्देश्य थे औद्योगिक उत्पादकता तकनीक के माध्यम से बढ़ाना कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय की स्थापना, प्रतिकूल व्यापार संतुलन, मुद्रा स्फीति दर नियंत्रण तथा आर्थिक दाम वृद्धि करना भी इस योजना के लक्ष्य रखे गये आर्थिक विकास दर का लक्ष्य 5.0% रखा गया जबकि वास्तविक उपलब्धि 6.01% रही।

## वार्षिक योजना (1990-92)

अर्थव्यवस्था की नवीन चुनौतियों के आ जाने के कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ नहीं हो सकी। इसके स्थान पर वार्षिक योजना आरंभ की गई। 1990-91 तथा 1991-92 में दो वर्षो के लिए वार्षिक योजना लागू की गई।

## आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-1997)

पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्यों में राजकोषीय घाटे का पूरा करना, भुगतान संतुलन को अनूकूल करना विदेशी मुद्रा भण्डार की कमी को दूर करना तथा मुद्रा स्फीति की दर को कम करना रखा गया। इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने हेतु नवीन आर्थिक सुधारों के रूप में लाईसेंसिंग नीति में उदारता लाना मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करने के साथ-साथ निजीकरण उदारीकरण तथा विश्वीकरण को अपनाना था ताकि देश

मे आर्थिक संवृद्धि दर को बढ़ाया जा सके गरीबी को कम किया जा सके तथा नए रोजगार के अवसरों का सृजन किया जा सके। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाने के साथ पर्यटन अवसंरचनात्मक विकास तथा मानव संसाधन विकास हेतु समुचित प्रयास किए जायें आर्थिक विकास का लक्ष्य 5.6% रखा गया वास्तविक उपलब्धि 6.8% रही। विश्व व्यापार संगठन की शर्तों पर 1995 में अनुबंध किया गया।

## नौवी पंचवर्षीय योजना (1997-2002)

नौवी योजना में गरीबी, बेरोजगारी उन्मूलन निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों में विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय जल उपलब्धता के साथ सामाजिक समानता एवं न्याय संबंधी लक्ष्य रखे गये इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा जनसंख्या नियंत्रण जैसे उद्देश्य भी सुनिश्चित किए गए इस योजना में सकल घरेलू उत्पाद दर निर्धारित लक्ष्य 5.4% के विरूद्ध 6.5% रही जबकि औद्योगिक विकास दर 2.1% के विरूद्ध 4.2% रही। आर्थिक विकास दर 7.1% निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध 6.8% रही।

## दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07)

दसवीं पंचवर्षीय योजना आर्थिक विकास दर का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 8% निर्धारित किया गया 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करने का निश्चय किया गया लिंग अनुपात में समग्रता साक्षरता दर तथा मजदूरी दर में समग्रता लाना रखा गया आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य 8.1% रखा गया वास्तविक उपलब्धि 7.7% रही।

## ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012)

उच्च शिक्षा दूरस्थ शिक्षा तथा औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा संस्थानों का विस्तार गरीबी उन्मूलन सेवा क्षेत्र में विस्तार लिंग समानता, पर्यावरण स्वच्छ पेय जल उपलब्धता इस योजना के उद्देश्य थे कृषि विकास दर को बढ़ाना थी के साथ आर्थिक विकास में वृद्धि भी लक्ष्य रखे गये कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में क्रमशः 4%, 10% तथा 9% की वृद्धि दर्ज की गई।

## वारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17)

राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा आर्थिक विकास दर 8% निर्धारित की गई वास्तविक दर 8.2% रही ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि भूमि क्षेत्र में वृद्धि बैंकिंग क्षेत्र में विस्तार तथा 50% ग्रामीण आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना लक्ष्य रखा गया।

## संदर्भ -


1. भारतीय अर्थव्यावस्था, मिश्रा एवं पुरी, हिमालयीन पब्लिशिंग, मुंबई, 2020
2. भारतीय अर्थव्यावस्था, रूद्रदत्त एवं सुंदरम, 2020
3. कुरूक्षेत्र, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दिल्ली 2021
4. योजना, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दिल्ली 2021